BIHAR FOUNDATION
BONDING • BRANDING • BUSINESS

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

+91 0612 2547371
+91 85442 99526
https:// biharfoundation. bihar.govt.in

सम्प्रति बिहार

बिहार फाउन्डेशन की प्रस्तुति

बिहार के महत्वपूर्ण अखबारों में छपे **सकारात्मक** समाचारों का संकलन

चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी सोमवार विक्रम संवत् 2079। 11 अप्रैल 2022

JKDESIGN 8369994118

6TH FLOOR, INDIRA BHAWAN, RCS PATH, PATNA-800001. BIHAR, INDIA.

45 झांकियां पहुंचीं डाकबंगला, सीएम ने उतारी आरती

रामनवमी पर रविवार को पूरी राजधानी श्रीराम की भक्ति में लीन रही। शहर के 45 इलाकों से झांकियां निकाली गईं, जो डाकबंगला चौराहा पहुंचीं। झांकियों का स्वागत डाकबंगला चौराहे के मुख्य मंच से किया गया। शाम में करीब साढ़े सात बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने सीता-राम की आरती उतारी। उन्हें अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति भेंट की गई। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम का अभिवादन किया।

विशेष कवरेज P 04,05

25 हजार से अधिक श्रद्धालु जुटे डाकबंगला पर

रविवार को पटना के डाकबंगला चौराहे पर झांकियों के स्वागत के दौरान सीता-राम की आरती उतारते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में हैं सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद, उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। • कुमार अनिल

सौजन्य से हिन्दुस्तान। पटना। 11.04.2022। पृष्ठ सं० 01

प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया स्थगित

डिप्टी सीएम ने तकनीकी त्रुटियों ठीक करने और अधिकारियों को समीक्षा करने को कहा

पटना | उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की पहल पर मछुआरा समाज के व्यापक हित में सहकारिता विभाग ने प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में पैक्सों के समरूप सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था को स्थगित कर दिया है। विगत दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल, सांसद अजय निषाद और मत्स्यजीवी समाज के दर्जनों प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर मछुआरा समाज की कठिनाइयों से अवगत कराया था, जिसमें मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में पैक्सों की तरह सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। ऑनलाइन माध्यम से गैर मछुआरा की भी सदस्यता के लिए आवेदन प्राप्त करने संबंधी कई परिवाद प्राप्त हुए थे। इसके बाद उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उक्त संबंध में तकनीकी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी तथा सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह एवं अन्य अधिकारियों से बात कर इसकी विस्तृत समीक्षा करने को कहा। उपमुख्यमंत्री की पहल पर सहकारिता विभाग ने इसे तत्काल स्थगित कर दिया है। परंपरागत मछुआरों की सूची उपलब्ध होने पर ही गहन समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा।

सौजन्य से दैनिक भास्कर। पटना। 11.04.2022। पृष्ठ सं० 04

पटना में अगले साल जून तक बनकर तैयार होगा देश का इकलौता डॉल्फिन रिसर्च सेंटर

16 अप्रैल से पाइलिंग होगी, काम प्रारंभ

30 करोड़ होंगे खर्च, केंद्र ने दी राशि

राज कुमार | पटना

देश का इकलौता डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का पटना में बनने जा रहा है। इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। गंगा के किनारे पटना यूनिवर्सिटी की करीब ढाई एकड़ जमीन पर निर्माण होगा। 16 अप्रैल से पाइलिंग होगी। करीब 30 करोड़ की लागत से जी प्लस टू बिल्डिंग का निर्माण होगा। भवन निर्माण विभाग द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। जून 2023 में इसका उद्घाटन करने का लक्ष्य है।

भवन निर्माण होने के बाद पिलर, दीवार या जमीन में किसी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए मिट्टी जांच की जा रही है। मिट्टी जांच की रिपोर्ट लैब से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए यह सेंटर बन रहा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने गंगा नदी से 200 मीटर की दूरी के अंदर डॉल्फिन सेंटर का निर्माण करने के लिए नगर विकास विभाग से अनुमति मांगी थी। नगर विकास विभाग ने 10 महीने पहले इसकी स्वीकृति दी। दरअसल, गंगा से 200 मीटर की दूरी पर भवन निर्माण करने पर रोक है। अनुमति मिलने के बाद प्रक्रिया में तेजी आई।

भवन निर्माण होने के बाद दिक्कत न हो इसके लिए हो रही मिट्टी जांच

नेपाल और बांग्लादेश के छात्र भी यहां करेंगे रिसर्च

भारत के बिहार, असम, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल में डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा के साथ ही चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियां डॉल्फिन के लिए बेहतर हैं। सेंटर खुलने के बाद देश के विभिन्न राज्यों के साथ-साथ नेपाल और बांग्लादेश के छात्र भी डॉल्फिन पर रिसर्च करने के लिए यहां आएंगे। वहीं यूनिवर्सिटी की जमीन पर सेंटर निर्माण होने से इसका फायदा पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों को सीधे मिलेगा। यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी शोध करने का मौका मिलेगा।

ऐसा दिखेगा सेंटर

2021 के सर्वे में गंगा नदी में 1448 डॉल्फिन दिखी

बिहार से गुजरने वाली गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या अधिक है। 2021 के सर्वे में गंगा नदी में 1448 डॉल्फिन दिखी थी। यूपी बॉर्डर चौसा से कटिहार के मनिहारी तक गंगा नदी में डॉल्फिन का सर्वे किया गया था। साथ ही गंगा के दो सहायक नदी कोसी और घाघरा नदी में डॉल्फिन का सर्वे हुआ था। इसमें 195 डॉल्फिन मिली थी।

जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया की वजह से आठ साल तक लटका रहा प्रोजेक्ट

वर्ष 2013 में केंद्र सरकार की तरफ से रिसर्च सेंटर के निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए मिले थे। इसके लिए पटना लॉ कॉलेज के पास गंगा तट पर पटना विश्वविद्यालय की भूमि चिह्नित की गई थी। लेकिन भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को लेकर यह प्रोजेक्ट कई वर्षों तक फंसा रहा। पांच अक्टूबर, 2018 को विश्व डॉल्फिन दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन नहीं मिलने पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर को भागलपुर स्थानांतरण करने की बात कही थी। इसके बाद पटना विश्वविद्यालय ने अपनी जमीन वन विभाग को दी। अब इसका बजट बढ़कर 30 करोड़ हो गया है।

प्रधान सचिव बोले

बिहार में तेजी से बढ़ रही है डॉल्फिन की संख्या

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का बिल्डिंग अगले साल बनकर तैयार हो जाएगी। भवन निर्माण विभाग के द्वारा बिल्डिंग निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार के गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या तेजी बढ़ रही है। डॉल्फिन के भोजन में कमी न हो इसके लिए गंगा नदी में छोटे मछलियों को मारने पर प्रतिबंध है। जूलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉल्फिन विशेषज्ञ डॉ. गोपाल शर्मा ने कहा कि गांगेय डॉल्फिन विलुप्त न हो इसके लिए पटना में रिसर्च सेंटर बहुत उपयोगी होगा। डॉल्फिन कहीं जख्मी मिलती है तो उसे लाकर इलाज किया जाएगा।

सौजन्य से दैनिक भास्कर | पटना | 11.04.2022 | पृष्ठ सं० 01

राज्य की 13 हजार किमी सड़कों की होगी ऑनलाइन निगरानी

विशेष

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार की 13 हजार किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की ऑनलाइन निगरानी होगी। एजेंसियों की ओर से कब-कब सड़कों की मरम्मत हुई और इंजीनियरों ने कब-कब उसका जायजा लिया, यह पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। सड़क मरम्मत में लापरवाही की शिकायत के बाद पथ निर्माण विभाग ने यह निर्णय लिया है। इन सड़कों की मरम्मत अभी ओपीआरएमसी (दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियों अनुरक्षण संविदा नीति) के तहत हो रही है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार साल 2019 से ही ओपीआरएमसी मॉडल लागू है। इसके तहत साल 2026 तक सड़कों की मरम्मत का जिम्मा एजेंसियों को दिया जा चुका है। लेकिन विभाग को आए दिन सड़क मरम्मत में लापरवाही की शिकायत मिलती रहती है। इन एजेंसियों की निगरानी इंजीनियरों को करनी है लेकिन वे भी इस काम में निष्क्रिय हो जा रहे हैं। कई स्थानों से इंजीनियर सड़क दुरुस्त होने की जानकारी भेज देते हैं लेकिन जब मुख्यालय से जांच कराई जाती है तो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं पाई जाती। यही कारण है कि अब तक कई एजेंसियों के साथ ही दोषी इंजीनियरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अब इंजीनियरों को मौके से ऑनलाइन रिपोर्ट भेजनी होगी। गौरतलब है कि ओपीआरएमसी के तहत राज्य के स्टेट हाईवे व मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की मरम्मत की जा रही है। सात साल के लिए 13063.26 किमी सड़कों की मरम्मत मद में 6654.27 करोड़ खर्च होने हैं। इस अवधि में कोई भी गड्ढबड़ी हुई तो निर्माण एजेंसी को ही उसे दुरुस्त करना है। मरम्मत अवधि में एजेंसी को सड़क निर्माण के बाद कम से कम एक बार कालीकरण (नवीनीकरण) अलग से करना जरूरी है। वारंटी पीरियड में केवल सड़कों पर उभरने वाले गड्ढों को भरने से काम नहीं चलेगा। सड़कों की सुरक्षा के साथ ही इसकी चिकनाई पर भी विशेष ध्यान देना है। सड़कों की बेहतर मरम्मत नहीं होने पर एजेंसी की राशि काट ली जाएगी। अगर महीने में दो शिकायत मिली और तय समय में उसे दुरुस्त नहीं किया गया तो पैसे की कटौती दो बार की जाएगी। गंभीर त्रुटियों पर कटौती का प्रतिशत 40 प्रतिशत तक है। सड़कों की मरम्मत हो रही है या नहीं, इसकी जांच चार स्तर पर की जानी है। स्थानीय इंजीनियरों के अलावा मुख्यालय, अंचल स्तर के अलावा उड़नदस्ता टीम को भी औचक जांच करनी है।

2025-26
तक यह नीति काम करेगी

मरम्मत पर नजर रखने को विशेष सॉफ्टवेयर

ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं हो, इसके लिए विभाग ने हर हाल में सड़कों को बेहतर रखने का निर्णय लिया है। इसके तहत कमांड एंड कंट्रोल रूम से सड़कों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। यह सुविधा विभाग में जल्द शुरू हो जाएगी। इस सिस्टम से यह देखा जा सकेगा कि कौन सी सड़क की मरम्मत कब-कब हुई है। साथ ही इंजीनियरों की भी इस प्रणाली से निगरानी हो सकेगी। कौन इंजीनियर किस सड़क की कितनी बार निरीक्षण कर रहे हैं, यह जानकारी भी विभाग को मिल जाएगी। विभाग की कोशिश है कि इस प्रणाली से राज्य की मरम्मत हो रही 13 हजार किलोमीटर सड़कों को बेहतर रखा जा सके।

एक नजर में ओपीआरएमसी

- 2018-19 से 2025-26 तक यह नीति काम करेगी
- 7731.61 किमी उत्तर बिहार की सड़कों की होगी मरम्मत
- 3623.27 करोड़ उत्तर बिहार की सड़कों पर होगा खर्च
- 5331.65 किमी दक्षिण बिहार की सड़कों की होगी मरम्मत
- 3031.49 करोड़ होगा दक्षिण बिहार की सड़कों पर खर्च

सौजन्य से हिन्दुस्तान। पटना। 11.04.2022। पृष्ठ सं० 02

थावे महोत्सवः बिखरी भोजपुरिया माटी की खुशबू

गोपालगंज

गोपालगंज, जिला संवाददाता। ...और मां आदि शक्ति दुर्गे व भक्त रहषु की पावन धरती स्वर, लय, ताल से झंकृत हो गई। अवसर था दो दिवसीय थावे महोत्सव के आगाज का। महोत्सव भोजपुरिया माटी व संस्कृति की खुशबू से सराबोर रहा। चैत्र की ढलती शाम सुरमई शाम में महोत्सव की महफिल ऐसी जमी कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। देर रात तक दर्शक कलाकारों की एक से बढ़ कर एक प्रस्तुति देख-सुन तालियां बजाते रहे। भावातिरेक में थिरकते रहे।

वाकई थावे का होमगार्ड मैदान भोजपुरीलोक संस्कृति की विविध लयात्मक अभिव्यक्तियों का गवाह बना। सूबे की प्रसिद्ध लोकगायिका शारदा सिन्हा के गीत पर दर्शक झूमते रहे। पंक्तियों को समवेत स्वर में दोहराते रहे। महोत्सव के पहले दिन थावे महोत्सव की सतरंगी छटा लोक संस्कृति को जगाए व जुगाए रखने का एहसास कराता रहा। महोत्सव में शामिल होने को यूपी समेत सूबे के अन्य जिलों से लोग ट्रेनों व अन्य वाहनों में भर-भर आए थे। यहां पहुंचे लोगों ने सबसे पहले थावे वाली मइया के दरबार में मत्था टेका और फिर इसके बाद शुरू हुआ महोत्सव के आगाज का इंतजार।

इस बीच न चिलचिलाती धूप का कोई असर था और न घर लौटने की चिंता। वे तो बस भोजपुरिया माटी की भीगी खुशबू से सराबोर होना चाहते थे। महोत्सव के पहले दिन नालंदा संगीत विकास संस्थान के कलाकार रंजीत कुमार एण्ड ग्रुप , लोकगायिका शारदा सिन्हा, लावण्या राज व साथी और गायिका सुश्री दीक्षा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। इसके पूर्व महोत्सव का उद्घाटन सूबे की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने किया। उद्घाटन सत्र में डीएम डीएम डॉ. नवल किशोर चौधरी समेत अन्य अधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया। विरासत से विकास की ओर पुस्तक व स्मारिका का विमोचन किया गया। मौके पर पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, खान व भूतत्व मंत्री जनक राम, पूर्व पर्यटन मंत्री रामप्रवेश राय, एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव, पर्यटन विभाग के सचिव संतोष कुमार मल्ल आदि थे।

थावे महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर रंगारंग कार्यक्रम पेश करती कलाकार व इनसेट में शारदा सिन्हा।

सौजन्य से हिन्दुस्तान | पटना | 11.04.2022 | पृष्ठ सं० 10

बिहार कोविड अपडेट

⇒ कुल सक्रिय मामलों की संख्या	15
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान नए पॉज़िटिव मामलों की संख्या	02
⇒ पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या	02
⇒ कुल वैक्सीनेशन	12,64,31,661
⇒ कम से कम एक डोस	6,91,50,877
⇒ पूर्ण वैक्सीनेटेड	5,63,36,281

बिहार फाउन्डेशन नेटवर्क

विदेश अवस्थित चैप्टर

कतर

दक्षिण कोरिया

जापान

हॉग कॉग

यू.ए.ई.

सिंगापुर

बहरीन

न्यूजीलैंड

कनाडा

यू.एस.ए.

ऑस्ट्रेलिया

सऊदी अरब

देश अवस्थित चैप्टर

मुम्बई	हैदराबाद	पुणे
चेन्नई	नागपुर	गुजरात
कोलकाता	वाराणसी	गोवा

पाठकों से अपील

बिहार फाउन्डेशन के जुड़ने के लिए

बिहार फाउंडेशन उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार की एक निबंधित सोसाईटी है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के बाहर बसे देश-विदेश अवस्थित बिहारी समुदायों को उनके स्वयं के बीच तथा गृह राज्य के साथ जोड़ने का है। वर्तमान मे बिहार फाउंडेशन के कुल 21 चैप्टर्स हैं. बिहार फाउंडेशन से जुड़ने के लिए नीचे दिए वेबसाइट पर जाकर Non Resident Bihari Registration पर क्लिक करें और उपलब्ध फार्म को भरकर जमा करें -

https://biharfoundation.bihar.gov.in.